भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी

प्रेस वक्तव्य

दिनांक–22 अप्रैल, 2017

पुलिस एवं केंद्रीय अर्ध–सैनिक बलों के जवानों व छोटे अधिकारियों से अपील!

पुलिस एवं अर्ध–सैनिक बलों के जवानों व छोटे अधिकारियों से भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी अपील करती है कि वे शोषक–शासक वर्गों – सामंती व देशी, विदेशी कॉरपोरेट घरानों की लूट व सत्ता को कायम रखने के लिए जान न गंवाएं, अपनी वर्गीय जड़ों को पहचानें एवं संघर्षरत जनता के साथ एकताबद्ध होवें.

मौत सबके लिए बराबर होती है. लेकिन सबकी मौत एक बराबर नहीं होती है. मुठ्ठीभर जन विरोधी व देशद्रोही शोषक–शासकों यानी सामंतियों, देशी, विदेशी कॉरपोरेट घरानों, लुटेरों, भ्रष्टाचारियों, हत्यारों, विभिन्न माफिया सरगनाओं के लिए जान गंवाना कोई अहमियत नहीं रखता है. उनके लिए जीना और मरना दोनों ही पंख से भी हल्के हैं, व्यर्थ हैं और निरर्थक हैं. जबकि व्यापक बहुसंख्य जनता खासकर शोषित–उत्पीड़ित जनता के लिए जान देना बहुत ही अहमियत रखता है. उनके लिए जीना व मरना हिमालय से भी भारी है, मूल्यवान है और सार्थक है. सशस्त्र बल ज़रा इस मायने में सोचे कि वे कैसे मर रहे हैं? किनके लिए जी रहे हैं और किनके लिए मर रहे हैं?

सरकारी सशस्त्र बलों के जवान संघर्षरत इलाकों में हमारी पीएलजीए–जन मुक्ति छापामार सेना के साथ झड़पों में–गोलीबारी में, माइन विस्फोटों में, बारूदी सुरंग विस्फोटों में, बूबी ट्रैप विस्फोटों में, कार्रवाई दस्तों की कार्रवाइयों में जान गंवा रहे हैं, बुरी तरह घायल होकर अपाहिज बन रहे हैं. मलेरिया जैसे जानलेवा बीमारियों का शिकार होकर जान से हाथ धो बैठ रहे हैं. विभागीय परेशानियों, आला अधिकारियों के असहनीय व पीड़ादायक बरताव से, बीवी–बच्चों व मां–बाप, भाई–बंधुओं के साथ समय गुजारने एवं तीज–त्योहार मनाने आदि के लिए छुट्टी न मिलने से लेकर कई तरीकों की पारिवारिक समस्याओं के चलते भारी मानसिक तनाव तथा अवसाद का शिकार होकर आत्महत्या करके अपनी जीवनलीला का स्वयं ही समाप्त कर रहे हैं. इन्हीं सब दबावों के चलते आपसी झगड़ों में उलझकर एक–दूसरे पर गोलियां चलाने, गश्त के दौरान माओवादी हमले की आशंका से पीड़ित व आतंकित होकर आपसी मुठभेड (क्रास फायरिंग) करने से भी जानें जा रही हैं. छुट्ठी न देने से लेकर गैर–जिम्मेदाराना व्यवहार, तानाशाहीपूर्ण व दबावपूर्ण व्यवहार के चलते अपने अफसरों पर गोली चलाना आदि भी जारी हैं. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 2015 में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के 60 जवानों ने आत्महत्या की. यह आंकड़ा साल–दर–साल बढ़ रहा है. आर्थिक तंगी व पारिवारिक विवाद को इन आत्महत्याओं की वजह बताते हुए ब्यूरो ने कहा कि 30 जवानों ने पारिवारिक व वैवाहिक कारणों से आत्महत्या की, जबकि 12 ने आर्थिक कारणों या कर्ज में फंसकर, चार ने जमीन–जायदाद के विवाद में फंसकर, एक ने नौकरी के कारण उपजा अवसाद के चलते मौत को गले लगाया था. 13 जवानों की खुदकुशी के कारणों का पता नहीं चलने की बात कही गयी है. दरअसल उपरोक्त आत्महत्याओं के लिए जो कारण बताए गए हैं, वो पूरी तरह सही नहीं हैं. सभी कारणों की जड़ एक ही होता है, नौकरी से उपजा भारी तनाव. इसे छुपाने के लिए अलग–अलग कारण बताए जाते हैं. संघर्ष इलाकों में तनावपूर्ण जिंदगी, परिवार और सगे–संबंधियों से लंबे समय तक दूर रहना, आर्थिक तंगी से ही बाकी तमाम कारण उपजते हैं.

ऑपरेशन ग्रीनहंट के शुरु होने के बाद से अब तक माओवादी छापामारों के हमलों में केंद्रीय अर्ध सैनिक बलों के लगभग 500 जवान व छोटे अधिकारियों की मौतें हुई हैं. यह एक सच्चाई है कि संघर्ष इलाकों में तैनात जवान हर पल दहशत में जीते हैं. परिवार वालों को हर पल इस आशंका में वक्त गुजारना पड़ता है कि कब कौनसी अनहोनी घट जाएगी और कब कौनसी मनहूस खबर सुनने को मिलेगी. कब ताबूत में लिपटी अपने लाड़ले की लाश दरवाजे पर दस्तक देगी. ऐसी 'महान' नौकरी जो खुद को और परिवारजनों को भारी मानसिक तकलीफ देती है, को लात मारकर हर साल हजारों युवा फोर्स से अपना नाता तोड़ रहे हैं. वर्ष 2013 में 4,186 और वर्ष 2014 में 6,700 जवानों ने फोर्स की नौकरी छोड़ दी थी. यह सिलसिला भी लगातार बढ़ रहा है जोकि एक अच्छा परिणाम है.

सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि दरअसल कोई अपने पसंद, इच्छा व शौक से पुलिस, अर्ध–सैनिक या सैन्य बलों में भर्ती नहीं होता है. क्योंकि पुलिस नौकरी कोई सम्मानजनक नौकरी तो है नहीं. जवानों को कोई बड़ी इज्जत तो नहीं

मिलती है. समाज में खासकर संघर्ष इलाकों में पुलिस की नौकरी को हेय दृष्टि से देखा जाता है. शोषक–शासक वर्गों के दमनकारी राज्य यंत्र के एक औजार के रूप में जनता के दमन में शामिल होने के चलते, गांवों पर हमलों, जनता की पिटाई, अवैध गिरफ्तारी, नाबालिग बच्चियों से लेकर बूढ़ी महिलाओं तक के साथ सामूहिक बलात्कार व हत्याएं, अमानवीय यौन अत्यचार, फर्जी मुठभेडों, घरों में आगजनी, संपत्ति को ध्वस्त करना एवं लुट–पाट करना, नरसंहारों को अंजाम देना आदि पाशविक व जघन्य करतूतों की वजह से पुलिस व अर्ध सैनिक बलों को आज देश की आम जनता सबसे घृणित, अपमानजनक व आक्रोशित नजर से देखती है. जबकि आप लोगों को देशभक्ति व जन सेवा का तमगा देकर लुटेरी सरकारों द्वारा उपरोक्त नीच कार्यों को अंजाम देने उकसाया जाता है. आप लोग उन्हीं कारनामों को देशभक्ति व जन सेवा के कार्यभार समझकर अंजाम देते हैं. फिर आप लोगों के प्रति जनता के मन में सद्भावना, सम्मान कैसे रह सकते हैं. इसीलिए जब भी हमारी पीएलजीए के हाथों सरकारी सशस्त्र बलों के जवानों व अधिकारियों की मौत होती है, जनता त्यौहार मनाती है, खुशियां बांटती है. जबकि हमारे लाल योद्धाओं की शहादत पर शोक मनाती है. उन्हें हर साल शहीद स्मृति सप्ताह के दौरान ससम्मान याद करती है. उनकी वीर गाथाओं को गाती है. उनके आदर्शों पर चलने का प्रण लेती है. उनकी लड़ाकू विरासत को जारी रखने के लिए अपनी संतानों को पीएलजीए में भर्ती के लिए भेजती है. जबकि आप लोग मजबूरी में, घोर अभाव में, कोई दूसरी नौकरी न मिलने की सूरत में, दुखी मन से सरकारी सशस्त्र बलों में भर्ती होते हैं. हम इस बात से अच्छी तरह अवगत हैं कि आप लोग गरीब व मध्यम किसान, मजदूर, पेट्टी बुर्जुआ परिवारों से आए हैं. आप लोग भी यह जानते व समझते हैं कि सशस्त्र बलों की नौकरियों में कोई धनी परिवार के बच्चे नहीं आते हैं. कोई राजनेता, पूंजीपति, बड़े ठेकेदार या व्यापारी, बड़े नौकरशाह के बच्चे पुलिस की नौकरी नहीं करते हैं. यदि कहीं, कोई करते भी हैं तो एसपी जैसे बड़े ओहदे पर.

आखिर गरीब व निम्न मध्यम वर्गों के युवाओं को सशस्त्र बलों की नौकरियां ही क्यों मिल रही हैं? बाकी नौकरियां क्यों नहीं? क्या दूसरे विभागों में नौकरियां नहीं हैं? इसे समझने के लिए सिर्फ छत्तीसगढ़ का उदाहरण ही काफी है. यहां विभिन्न सरकारी विभागों में पिछले 13 सालों से दसियों हजार पद रिक्त हैं. लेकिन शिक्षाकर्मी भर्ती छोड़कर बाकी विभागों में कोई भर्ती नहीं हुई है. भर्ती लगातार जारी है तो सिर्फ पुलिस, एसपीओ, विशेष बटालियन–बस्तर बटालियन, अर्ध सैनिक बलों में. सरकारें जानबूझकर जन विरोधी नीतियों पर अमल करते हुए राज्य और देश के युवाओं को सम्मानजनक नौकरियों से वंचित करके उनकी बेहद गरीबी का नाजायज फायदा उठकर सिर्फ और सिर्फ सशस्त्र बलों में ही जाने मजबूर कर रहे हैं.

दरअसल सशस्त्र बलों की नौकरियां इस देश व राज्य के सत्ताधारी शोषक–शासक वर्गों की सेवा, उनके शोषण–दमन व उत्पीड़न को जारी रखने के लिए ही हैं. हमारे देश की जनता को असली मायने में आजादी नहीं मिली है. यद्यपि देश से अंग्रेज चले गए लेकिन आज भी साम्राज्यवादी लूट यानी नव औपनिवेशिक तरह का अप्रत्यक्ष शोषण, शासन व नियंत्रण बेरोकटोक जारी है. हमारे देश के शासक वर्ग हैं–जमींदार, दलाल नौकरशाही पूंजीपति जो साम्राज्यवादियों के साथ सांठगांठ किए हुए हैं. इसीलिए सशस्त्र बलों की विधि है, इन शासक वर्गों की सेवा करना, उनकी गुलामी करना. यानी जमींदारों, देशी, विदेशी कॉरपोरेट घरानों, बड़े ठेकेदारों व व्यापारियों, पुलिस–प्रशासनिक नौकरशाहों, राजनेताओं, माफिया सरगनाओं की सुरक्षा, उनकी संपत्ति की रक्षा करना, उनके शोषण व दमन को जारी रखना, उनकी जन विरोधी नीतियों पर अमल के खिलाफ व अपनी जायज मांगों को लेकर आन्दोलनरत लोगों का बेरहमी से दमन करना, उनके संकट के बोझ को हमारे देश की जनता के कंधों पर लादने की कवायद के तहत जनता खासकर आदिवासी, किसानों की जल–जंगल–जमीन व देश के संसाधनों को लूटने व लुटाने में सहयोग करना, जन आन्दोलनों, मानवाधिकार आन्दोलनों, विस्थापन विरोधी आन्दोलनों, विभिन्न तबकाई आन्दोलनों व शोषणविहीन समतामूलक समाज व्यवस्था की स्थापना के लिए जारी माओवादी जनयुद्ध का दमन करना. मुठ्ठीभर रुपए देकर शोषित व पीड़ित वर्गों के ही लोगों को उनकी सेवा में लगाया जा रहा है. अपनी ही उंगलियों से अपनी आंखे फोड़वाने की कुटिल नीति है, यह. आज सशस्त्र बल संघर्ष इलाकों में जल–जंगल–जमीन–इज्जत–अधिकार के लिए जारी जन आन्दोलनों खासकर आदिवासी आन्दोलनों पर कहर बरपा रहे हैं. शोषकों की रक्षा में वे अग्रिम पंक्ति में रहकर लड़ रहे हैं. इसीलिए जनता व जन मुक्ति छापामार सेना के हमलों का अनिवार्य रूप से शिकार हो रहे हैं. इस बात को अच्छी तरह समझें.

हमारे देश के शोषक–शासक वर्गों की सरकारें दरअसल क्या कर रही हैं, जरा सोचिए. पिछले 70 सालों की तथाकथित आजादी के बाद भी आज देश में गरीबी, अस्वस्थता, अशिक्षा, बेरोजगारी, आवासहीनता, भूखमरी, बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव, पेयजल व सिंचाई का अभाव विद्यमान हैं. देशी, विदेशी कॉरपोरेट घरानों के लिए जनता को खासकर आदिवासियों, किसानों को उनके जल–जंगल–जमीन से बेदखल किया जा रहा है. संसाधनों की सस्ती लूट के लिए देश को बेचते हुए एमओयू किए जा रहे हैं. आदिवासी अस्तित्व, अस्मिता, आत्मसम्मान को नष्ट किया जा रहा है. विशेषकर केंद्र में ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवादी संघ परिवार की भाजपा के सत्तारूढ़ होने के बाद 'मेक इन इंडिया', 'डिजिटल इंडिया' जैसे दसियों आकर्षक व लोक लुभावन योजनाओं की घोषणा करके उन पर जबरन अमल किया जा

रहा है जिससे देश की सार्वजनिक संपत्ति की बेरोकटोक लूट को संभव बनाया जा रहा है. यह ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवादी संघ गिरोह देश को उग्र हिन्दू राष्ट्र बनाने की कवायद कर रही है. देश के आदिवासियों, दलितों, धार्मिक अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, महिलाओं के खिलाफ यह गिरोह फतवें जारी कर रहा है. उनके खान–पान की आदतों, रहन–सहन, पहनावा–ओढ़ावा, रीति–रिवाज, देवी–देवताओं, भाषा–बोलियों एक शब्द में कहा जाए तो उनके आर्थिक व सांस्कृतिक जीवन पर तमाम तरह की पाबंदियां लगा रहा है. ये तमाम योजनाएं वास्तव में देशी, विदेशी पूंजीपति घरानों के फायदे के लिए ही हैं. इसीलिए ग्रीनहंट दमन जोकि जनता पर युद्ध ही है, जारी है. इसे अंजाम देने के लिए ही सरकारी सशस्त्र बलों में अबाध गति से वृद्धि की जा रही है. संघर्ष इलाकों में पुलिस व अर्ध–सैनिक बलों की तैनाती इसी का हिस्सा है. वरना एकबार सोचे कि बस्तर के जंगलों में, 'अबूझ'माड के घने जंगल व पहाड़ों में या छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र के अंदरूनी इलाकों में किस देश की सरहदें हैं कि बीएसएफ को तैनात किया गया है? यहां कौनसा तिब्बत है कि आईटीबीपी तैनात है?

अपनी सेवा व गुलामी करने वाले सशस्त्र बलों को आखिर शासक वर्ग किस नजर से देखते हैं? जानवरों से ज्यादा अहमियत नहीं देते हैं. आप तो अच्छे से वाकिफ हैं कि देशभर में जितने भी विशेष बलों का गठन किया गया है, सभी का नाम जानवरों का ही नाम दिए गए हैं. ग्रे हाउण्ड्स (बूरे रंग का शिकारी कुत्ता), कोबरा(नाग सांप), हॉक (बाज़) फोर्स, ब्लैक कैट (काली बिल्ली) कमांडो आदि. आप लोगों के साथ व्यवहार भी इन्सानों जैसा कहां किया जाता है? जानवरों जैसा ही सलूक किया जाता है जिससे आप लोग भली–भांति परिचित हैं. जिंदा रहते समय वेतन के नाम पर कुछ रुपए और मरने पर मुठ्ठीभर रुपए फेंकते हैं. अनुकंपा नियुक्ति के नाम पर अगली पीढ़ी को भी अपनी सेवा में लगा देते हैं. ये रुपए भी कोई पूंजीपति, मंत्री या आला अधिकारी की जेब के नहीं हैं. ये जनता की ही संपत्ति का हिस्सा है. आला अधिकारियों के हर तरह का दबाव, उनके घरेलू कार्य सहित तमाम सेवाएं देना, उनके गाली–गलौच यहां तक कि मार–पीट भी सहना, नौकरी के नाम पर यही सब होता है. सरकार के शह पर संघर्षरत जनता जोकि हमारी अपनी ही है, के साथ अमानवीय व्यवहार करने बाध्य होते हैं.

दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी सरकारी सशस्त्र बलों के जवानों व छोटे अधिकारियों से आग्रह करती है कि वे हमारे देश की वास्तविक परिस्थितियों से, विशेषकर संघर्ष इलाकों की सच्चाई से वाकिफ होवें. लुटेरी सरकारों के शोषणकारी व दमनकारी नीतियों से अवगत हो जावें. दमनकारी राज्ययंत्र के हिस्से के तौर पर सशस्त्र बलों का शोषक–शासक वर्ग बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं. आप जनता के दुश्मन वर्ग के नहीं हो. लेकिन दुश्मन आप लोगों को ही सामने रख रहा है. हमारी पार्टी अपील करती है कि आप लोग इस साजिश को अच्छे से समझें. शोषकों के हितों की रक्षा के लिए, उनके फायदे के लिए, उनके हाथों में औजार न बने. अपनी वर्गीय जड़ों व वर्गीय हितों को पहचानकर व्यवहार करें. अपनी ही जनता पर कहर बरपाने से बचें. भारी तनावपूर्ण नौकरी को लात मारकर जाएं. इज्जत से जीने की नौकरी के लिए लड़ें. जल–जंगल–जमीन–संसाधनों को बचाने के लिए जारी जनयुद्ध की हर संभव मदद करें. अपने अस्तित्व, अस्मिता, आत्मसम्मान के लिए आन्दोलनरत जनता के पक्ष में खड़े होवें. अनावश्यक अपने प्राणों को न गंवाएं. आत्महत्या तो बिल्कुल ही न करें. यह समस्याओं का कोई समाधान नहीं है. पीएलजीए में भर्ती होकर वर्ग संघर्ष में अपनी वर्गीय जनता के पक्ष में सकारात्मक भूमिका निभाएं. शोषकों, भ्रष्ट राजनेताओं, बड़े मालगुजारों, बड़े पूंजीपतियों, विदेशी कंपनियों के खिलाफ निशाना साधें.

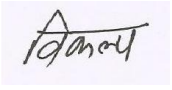

(विकल्प)
प्रवक्ता
दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)